ernments for their Development Schemes and to different Central authorities. For major irrigation projects, steel was allotted by the Central Water & Power Commission and for the minor irrigation projects/ schemes by the State Government. Demands received from both these authorities include all projects/ schemes and separate statistics regarding the demand and supplies for irrigation projects alone are not available. At present, allocations are made and quotas issued only for sheets.

उत्तर प्रदेश को लोहा

२०८६. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० ब० सिंह :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई योजनाओं के लिये १९५७ से १९६० तक वर्षवार कितने लोहे की मांग की ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने वर्षवार कितना लोहा दिया ?

इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री (श्री सी० मण्यम) (क) और (ख). मांगें वित्त-वर्षवार प्राप्त की जाती है और तदनुसार आवंटन किया जाता है । सम्भवतः माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार को विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिये इस्पात न कि लोहे (अपिवम लोहे) की मांग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ।

भारत सरकार प्रत्येक योजना के लिये पृथक विनिधान नहीं करती । राज्य सरकारों तथा विभिन्न केन्द्रीय प्राधिकारियों को विकास योजनाओं के लिये इकट्ठे कोटे दिये जाते हैं । बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिये इस्पात का विनिधान सेंट्रल वाटर और पावर कमिशन द्वारा किया जाता है और छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये राज्य सरकारों द्वारा । इन दोनों प्राधिकारियों से प्राप्त हुई मांगों में सिंचाई की सभी योजनायें सम्मिलित होती है और केवल सिंचाई योजनाओं के लिये पृथक पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इस समय केवल चादरों का विनिधान किया जाता है तथा कोटे दिये जाते हैं ।

Low temperature Garbonisation Plant

2091. Shri Eswara Reddy: Will the Minister of **Mines and Fuel** be pleased to state:

(a) at what stage the proposal is to set up a low temperature carbonisation plant at Kothagudium; and

(b) the foreign exchange required for this plant?

The Minister of Mines and Fuel (Shri K. D. Malaviya): (a) and (b). Taking into consideration and expert advice available, it was proposed by the Government of India to set up three low temperature carbonisation plants at Jambad (Raniganj), Kothagudium (Singareni) and South Karampura in the public sector. However, there being a large unbridged gap in the total proposed outlay on the III plan and the financial resources in sight, the Government of India have not found it possible to make financial provision for this purpose.

Welfare of S.Cs. and S.Ts. in Punjab

2092. Shri Daljit Singh: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether any amount was surrendered as unspent by the Punjab Government during the Second Five Year Plan period under the Centrally sponsored programme for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) if so, the amount surrendered, year-wise?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) Yes.